हरियाणा राज्य और अन्य,-अपीलकर्ता

बनाम:

विनोद कुमार एवं अन्य, प्रतिवादी

नियमित द्वितीय अपील को. 1980 का 2930

14 अक्टूबर 1985.

पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम (1953 का X)-धारा 2(3), 5-बी और 25-पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा नियम, 1956-नियम 6-हरियाणा भूमि स्वामित्व सीमा अधिनियम (1972 का XXVI)-धारा 26 -कलेक्टर संबंधित भूमि मालिकों को सुने बिना अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करता है - ऐसा आदेश - चाहे वह शून्य हो - प्रभावी पक्ष जिन्हें ट्रिब्यूनल ने नहीं सुना है - चाहे उसके आदेश से बंधे हों - उपचार उनके लिए खुले हैं - ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती देने वाला मुकदमा एक आदेश - क्या पंजाब अधिनियम की धारा 25 के मद्देनजर कायम रखने योग्य है।

निर्णय, कि निर्णय/आदेश दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, रेम में निर्णय और व्यक्तिगत रूप से निर्णय। पहला पूरी दुनिया को बांधता है जबकि बाद वाला केवल पार्टियों को बांधता है। संबंधित निर्णय/आदेश वे हैं जो दिवाला, एडमिरल और आदि जैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारियों या न्यायालयों द्वारा पारित किए जाते हैं।वैवाहिक पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 के तहत अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार ऐसी प्रकृति का नहीं है कि इसके तहत पारित आदेश बड़े पैमाने पर जनता को बाध्य करेंगे। जाहिर है, वे व्यक्तिगत निर्णय/आदेश हैं। उनकी प्रकृति के बारे में मौलिक सिद्धांत यह है कि वे केवल पार्टियों को या उसमें नामित व्यक्तियों को ही इससे जोड़ते हैं। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जो न तो पक्षकार है और न ही ऐसे आदेश में नामित है, कानून की नजर में आदेश अप्रभावी और गैर-स्थायी है और इस तरह वह इसे रद्द करने के लिए कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी निर्णय या आदेश के लिए उपयोग किए जाने पर 'शून्य' या 'शून्य' शब्द का सख्ती से उपयोग तब प्रासंगिक होगा जब कोई व्यक्ति पक्षकार हो या निर्णय या आदेश में नामित हो, क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति ही इसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। जैसा भी मामला हो, शून्य घोषित कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है, उसे आदेश को रद्द करने या उसे शून्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि आदेश उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा जो पक्षकार हैं या उसमें नामित हैं और उपाय केवल घोषणा प्राप्त करना होगा। जहां तक उनका सवाल है, यह आदेश प्रभावी और अप्रभावी था।

निर्णय, कि यदि संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए बिना सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो आदेश अमान्य होगा और सिविल न्यायालय में चुनौती के लिए खुला होगा, भले ही उक्त क़ानून स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता हो। ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता या वैधानिकता को चुनौती देने के लिए एक मुकदमे पर विचार करें। किसी व्यक्ति को कलेक्टर के उस आदेश के खिलाफ कोई अपील या समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें वह एक पक्षकार नहीं था, लेकिन भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वह अपील दायर कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुमति या समीक्षा के लिए कदम, तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आदेश के साथ घोषणा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने का समवर्ती या वैकल्पिक उपाय 'जहां तक उसका संबंध था, गैर-स्थायी था, द्वारा वर्जित किया जाएगा पंजाब अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैकल्पिक या समवर्ती उपचारों के मामले में पार्टी उनमें से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, उपचार का अस्तित्व, यदि कोई हो, मुकदमे के उपचार से वंचित नहीं करेगा यदि यह अन्यथा उसके लिए उपलब्ध था। इस प्रकार, यह माना जाता है कि संबंधित भूमि मालिक को सुनवाई का अवसर दिए बिना भूमि को अधिशेष घोषित करने वाला कलेक्टर का आदेश, जैसा कि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा नियम, 1956 के नियम 6 द्वारा परिकल्पित है, निरर्थक है और एक मुकदमा है। ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती देना अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है।

(मामले को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था - माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया के दिनांक 30 जुलाई, 1982 के आदेशों के तहत। डिवीजन बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री शामिल थे। न्यायमूर्ति एस.एस. कांग ने 24 सितंबर, 1982 को इस मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश एस.एस. संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग और शामिल थे। माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल ने फिर भी 4 अगस्त, 1983 को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। बड़ी पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश 'श्री प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल, माननीय शामिल थे। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग, माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल और माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना ने 14 अक्टूबर, 1985 को इस मामले में शामिल प्रश्न का सकारात्मक निर्णय लिया। माननीय श्रीमान की खंडपीठ में शामिल थे। न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. 17. सहगल ने अंततः 3 दिसंबर, 1985 को मामले का फैसला किया)।

श्री 17. के. जैन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा की अदालत के 1 सितंबर, 1980 के फैसले के खिलाफ नियमित दूसरी अपील, जिसमें श्री डी. डी. यादव, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सिरसा के 24 अगस्त, 1979 के फैसले को पलट दिया गया। 31 जनवरी के निर्णय की घोषणा के लिए संपूर्ण लागत के साथ वादी का मुकदमा। कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र, सिरसा की धारा 1962 शून्य और निष्क्रिय है और प्रतिवादियों को दिनांक 31 जनवरी, 1962 के आक्षेपित आदेश द्वारा अधिशेष या किरायेदारों के लिए अनुमेय क्षेत्र घोषित की गई वाद भूमि का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादियों को वाद का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा है।

(1) उत्तरदाताओं ने यह घोषणा करने के लिए यह मुकदमा दायर किया कि कलेक्टर का 31 जनवरी 1962 का आदेश, जिसमें उनके पिता गोबिंद पार्षद के हाथों में 87.14 एकड़ को अधिशेष क्षेत्र और 138.31 एकड़ को किरायेदार के लिए स्वीकार्य क्षेत्र घोषित किया गया था, अमान्य और निष्क्रिय था। हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, हरियाणा अधिनियम) के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं को उक्त भूमि का उपयोग करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए। वादपत्र में लगाए गए भौतिक आरोप यह थे कि उत्तरदाताओं और उनके पिता गोबिंद पार्षद ने एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया और उनके पास जिले के गांव फतेहपुरिया में स्थित 500 एकड़ कृषि भूमि थी।

15 अप्रैल, 1953 से पहले सिरसा, वह तारीख जिस दिन पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट (इसके बाद पंजाब एक्ट कहा जाएगा) लागू किया गया था। वर्ष 1953 में, गोबिंद पार्षद ने स्वयं पारिवारिक समझौते के माध्यम से 170 एकड़ भूमि अपनी पत्नी के नाम पर हस्तांतरित कर दी। इसके बाद, वर्ष 1954 में कुछ समय के लिए पारिवारिक विभाजन हुआ, जिससे शेष भूमि का 3/5 हिस्सा विनोद कुमार, रतन लाई और ओम प्रकाश, प्रतिवादियों के हिस्से में आ गया, जबकि 2/5 हिस्सा गोबिंद पार्षद और उनके चौथे बेटे अनिल के पास रहा। 14 अप्रैल, 1976 को कुमार, गोबिंद पार्षद की मृत्यु हो गई और उनके पास मौजूद जमीन उनके बेटे अनिल कुमार और उनकी विधवा के नाम पर बदल दी गई।

(2) कलेक्टर के उक्त आदेश को मुख्य रूप से दो आधारों पर चुनौती देने की मांग की गई थी कि इस तथ्य के बावजूद कि वादी ऊपर बताई गई सीमा तक भूमि के मालिक दर्ज किए गए थे, घोषणा से पहले कलेक्टर द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अधिशेष क्षेत्र और किरायेदार के अनुमेय क्षेत्र और कुल जोत में से 432 बीघे, 14 बिस्वा भूमि बंजार कादिम, बंजार जदीद और ग़ैर मुमकिन थी और इस तरह "भूमि" नहीं थी, जैसा कि पंजाब अधिनियम में परिभाषित किया गया है। भूस्वामियों की कुल जोत में गिना जाएगा।

(3) इस मुकदमे का अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था और उठाए गए बचावों में से एक जिसके साथ हम केवल इस संदर्भ में चिंतित हैं, वह यह था कि मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हरियाणा की धारा 26 के प्रावधानों के आधार पर रोक दिया गया था। कार्यवाही करना। हालाँकि, प्रश्न में पंजाब अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, जो कि वर्तमान मुकदमे को नियंत्रित करने वाला प्रासंगिक प्रावधान है। ट्रायल कोर्ट ने राज्य की दलीलों को बरकरार रखा और मुकदमा खारिज कर दिया। अपील

पर, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया जिसके कारण राज्य द्वारा यह नियमित दूसरी अपील दायर की गई।

(4) प्रारंभ में अपील की सुनवाई एक डिवीजन बेंच द्वारा की गई थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धौंकल शेओ राम, बनाम में पूर्ण बेंच का निर्णय सही था। मन कौरी राम जस और अन्य, (1) को उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा चुनौती दी गई थी, मामले को तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ को भेजा गया था। पूर्ण पीठ की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मद्देनजर धौंकल शेओ राम के मामले (सुप्रा) पर पुनर्विचार की आवश्यकता हैसंदर्भ आदेश में देखा गया, निम्नलिखित प्रश्न को बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

"क्या संबंधित भूमि मालिक को सुनवाई का अवसर दिए बिना भूमि को अधिशेष घोषित करने वाला कलेक्टर का आदेश, जैसा कि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा नियम, 1956 के नियम 6 द्वारा परिकल्पित है, अमान्य है और क्या इसकी वैधता को चुनौती देने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया है? सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर अधिनियम की धारा 25 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश कायम रखने योग्य है?"

हरनेक सिंह और अन्य मामले में पांच जजों की बेंच। पंजाब राज्य और अन्य (2), ने आधिकारिक तौर पर कहा कि एक बड़े भूस्वामी द्वारा भूमि का हस्तांतरण हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वैध है और धारा 10-ए (बी) के प्रावधानों का एकमात्र प्रभाव है। पंजाब अधिनियम में यह है कि यदि भूमि, हस्तांतरण की विषय-वस्तु अधिनियम के प्रारंभ में अधिशेष क्षेत्र का हिस्सा है, तो स्थानांतरण किरायेदारों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करने के राज्य के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। आगे यह माना गया कि ऐसा हस्तांतरितकर्ता एक इच्छुक पक्ष था और उसे किसी भी भूमि को अधिशेष घोषित करने का आदेश पारित करने से पहले कलेक्टर द्वारा सुने जाने का अधिकार था। नतीजतन, जब कलेक्टर ने आक्षेप पारित कर दिया . नतीजतन, जब कलेक्टर ने 31 जनवरी, 1962 को आक्षेपित आदेश पारित किया, तो कुल भूमि में से 170 एकड़ जमीन गोबिंद पार्षद की पत्नी के पास थी और शेष 330 एकड़ जमीन में वादी 4/ की सीमा तक मालिक थे। 5वां शेयर और गोबिंद पार्षद एल./5वां शेयर. माना जाता है कि, आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले कलेक्टर द्वारा वादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था। इन तथ्यों पर जो परेशान करने वाला सवाल खड़ा हुआ है वह यह है कि जहां तक उन प्रभावी पक्षों का सवाल है जिनकी बात नहीं सुनी गई है, विवादित आदेश की वास्तविक प्रकृति क्या है और क्या वे कानूनी रूप से आदेश से बंधे हैं जब तक कि इसे रद्द न कर दिया जाए और यदि नहीं तो क्या उनके लिए उपचार खुले होंगे।

(5) व्यापक रूप से बोलते हुए, 'निर्णय/आदेश के दो प्रकार होते हैं, अर्थात् रेम में निर्णय और व्यक्तिगत रूप से निर्णय। पहला पूरी दुनिया को बांधता है जबकि बाद वाला केवल पार्टियों को बांधता है। रेम में निर्णय/आदेश दिवाला, एडमिरल और वैवाहिक जैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारियों या न्यायालयों द्वारा पारित किए गए हैं। पंजाब अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार इस प्रकार का नहीं है कि इसके तहत पारित आदेशबड़े पैमाने पर जनता को बांधेगा। जाहिर तौर पर वे व्यक्तिगत रूप से निर्णय/आदेश हैं। उनकी प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत यह है कि वे केवल पार्टियों को या उसमें नामित व्यक्तियों को ही बांधते हैं। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जो न तो पक्षकार है और न ही ऐसे आदेश में नामित है, कानून की नजर में आदेश अप्रभावी और गैर-स्थायी है और इस तरह वह इसे रद्द करने के लिए कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी निर्णय या आदेश के लिए उपयोग किए जाने पर 'शून्य' या 'शून्य' शब्द का सख्ती से उपयोग तब प्रासंगिक होगा जब कोई व्यक्ति पक्षकार हो या निर्णय या आदेश में नामित हो, क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति ही इसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। जैसा भी मामला हो, शून्य घोषित कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है, उसे आदेश को रद्द करवाने या उसे शून्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि आदेश उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा जो पक्षकार हैं या उसमें नामित हैं और उसका उपाय केवल 9 घोषणा प्राप्त करना होगा। जहां तक उनका सवाल है तो यह आदेश अप्रभावी और ईमानदार था। धौंकल श्यो राम के मामले में (सुप्रा) यह बुनियादी है, सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया और इसके बजाय, यदि हम विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, तो तर्क गलत आधार पर आगे बढ़ा कि चूंकि कलेक्टर के पास भूमि मालिक

के अधिशेष क्षेत्र को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था, गैर- किरायेदार को नोटिस जारी करने से उसका आदेश रद्द नहीं होगा और आदेश किरायेदार पर बाध्यकारी होगा। यदि भूस्वामी अपने आरक्षित क्षेत्र में पट्टे पर दी गई किसी भी भूमि को शामिल करता है, तो किरायेदार को सुनवाई का अधिकार होगा क्योंकि आरक्षण का आदेश अनावश्यक रूप से भूस्वामी को ऐसे क्षेत्र से बेदखल करने का अधिकार देता है। यदि भूमि मालिक किरायेदारों के साथ पट्टे पर कोई क्षेत्र शामिल नहीं करता है, तो बाद वाले को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा और मकान मालिक के अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण का आदेश उनकी पीठ पर पारित होने पर भी पूरी तरह से मान्य होगा। भूस्वामी के आरक्षित क्षेत्र में पट्टे के तहत क्षेत्र सहित कलेक्टर का आदेश हालांकि अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन किसी भी किरायेदार को बाध्य नहीं करेगा, जिसका क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जब तक कि उसे नोटिस जारी नहीं किया जाता है या उसका नाम नहीं दिया जाता है। कलेक्टर का आदेश. कुछ इसी तरह का प्रश्न पंजाब राज्य और अन्य बनाम में उठा। अमर सिंह और. एक और (3), और डौंकल शेओ राम के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम, उस मामले में निर्णय द्वारा *संभावित रूप से खारिज कर दिया गया है। वहां क्या हुआ कि श्रीमती. निर्धारित तिथि यानी 15 अप्रैल, 1953 को लछमन एक बड़े जमींदार थे। उनके दामाद अमर सिंह और उनके भाई इंद्राज ने खुद को जमींदार के आरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के किरायेदार होने का दावा किया। पंजाब की धारा 18 के तहत एक आवेदन

इसकी खरीद के लिए अधिनियम और सक्षम प्राधिकारी, सहायक कॉयर लेक्टर द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। विक्रय प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त किरायेदारों ने भू-स्वामी के अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण संबंधी कार्यवाही के दौरान कलेक्टर के समक्ष स्वयं को उनके द्वारा खरीदी गई भूमि का स्वामी होने का दावा किया। राज्य की ओर से उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि वह पंजाब अधिनियम की धारा 18 के तहत कार्यवाही में पक्षकार नहीं होने के कारण, क्षेत्र के किरायेदारों को खरीद की अनुमति देने वाले निर्धारित प्राधिकारी के आदेश से बाध्य नहीं है, लेकिन इसके लिए वह खरीद ज़मीन मालिक के अधिशेष क्षेत्र का हिस्सा थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के तहत, जब किसी किरायेदार द्वारा किसी बड़े जमींदार का क्षेत्र खरीदने के लिए सहायक कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन किया जाता है, तो उसे यह करना आवश्यक है। भूमि मालिक और उक्त भूमि में रुचि रखने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करें। यदि किरायेदार द्वारा खरीदा जाने वाला क्षेत्र उसके अनुमेय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है या नियत समय के बाद वह उस पर बस गया है, 1953, ऐसा क्षेत्र अधिशेष क्षेत्र का हिस्सा होगा और राज्य स्पष्ट रूप से एक इच्छुक पक्ष होगा जो खरीद आवेदन की अनुमति से पहले उक्त धारा के तहत नोटिस का हकदार होगा। दौंकल शेओ राम के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम के अनुसार, राज्य को नोटिस दिए बिना किरायेदार के पक्ष में पारित खरीद का आदेश राज्य पर बाध्यकारी होगा और केवल उसके उदाहरण पर रद्दीकरणीय होगा क्योंकि निर्धारित प्राधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र था ऐसे आवेदन का प्रयास करें और पंजाब अधिनियम की धारा 18 के तहत इसकी अनुमति दें। लेकिन अमर सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य, जो आदेश से गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित था, लेकिन इसका पक्ष नहीं था, उस आदेश से बाध्य नहीं होगा। आगे यह माना गया कि जो राज्य कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, उसे अपील का अधिकार नहीं था क्योंकि आम तौर पर नियम यह है कि डिक्री से प्रतिकूल रूप से प्रभावित मुकदमे का केवल एक पक्ष, यदि उसका कोई प्रतिनिधि-हित, अपील कर सकता है समीक्षा के लिए एक अपील या याचिका जैसा कि नीचे दिए गए अनुच्छेद 32 से स्पष्ट होगा।

"अनुलग्नक 'ए' जैसा आदेश आम तौर पर केवल पार्टियों को बाध्य करता है और यहां राज्य जो अपीलकर्ता है, आदेश से गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त है, लेकिन इसका पक्ष नहीं है। इसलिए, यह राज्य को उचित शक्ति से बाध्य नहीं कर सकता। श्री ढींगरा द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि कोई आधार था तो राज्य समीक्षा की अपील के माध्यम से आगे बढ़ सकता था और आदेश को रद्द करवा सकता था और ऐसा नहीं करने पर वह आदेश से बंधा हुआ था। वस्तुतः, राज्य, जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, को अपील का अधिकार नहीं है। यह सामान्य नियम यह है कि डिक्री से प्रतिकूल रूप से प्रभावित मुकदमे का केवल एक पक्ष या उसका कोई हितैषी प्रतिनिधि ही अपील दायर कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति, जो पक्षकार नहीं है, अपीलीय अदालत की इजाजत से

अपील कर सकता है, यदि वह फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और यदि यह धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 के तहत पुनर्निर्णय के रूप में उस पर बाध्यकारी होगा' (देखें) मुल्ला सिविल प्रक्रिया संहिता, 13- संस्करण, खंड I, पृष्ठ 421) पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 82, जिसे शायद अधिनियम के तहत भी किसी पार्टी द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा आवेदन की बात करती है। इस प्रकार धारा 18 के तहत समीक्षा या अपील के किसी भी अधिकार का उपयोग राज्य द्वारा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।"

(6) भले ही तर्कों के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि आक्षेपित आदेश केवल शून्यकरणीय है और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी होगा जब तक कि इसे शून्य घोषित नहीं किया जाता है या रद्द नहीं किया जाता है, क्या यह कहा जा सकता है कि उनके लिए एकमात्र उपाय खुला है पंजाब अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क करने और नियमित मुकदमे का समाधान पंजाब अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों द्वारा वर्जित होगा। इस संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित किया गया है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मास्क एंड कंपनी, (4) इस प्रकार यह स्थापित कानून है कि सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बहिष्कार या तो होना चाहिए,स्पष्ट रूप से व्यक्त या स्पष्ट रूप से निहित। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया हो, सिविल न्यायालयों के पास उन मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है जहां अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।उक्त नियम को सुप्रीम कोर्ट ने कटिकासा चिंतामन डोरा और अन्य बनाम में दोहराया था। गुआत्रेड्डी अन्नामनायडु (5), निम्नलिखित शब्द:

"इस सवाल पर फैसला देने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में एक स्पष्ट बाधा है कि क्या 'कोई इनाम गांव'एक 'इनाम संपत्ति' है या नहीं, और 1948 के मद्रास अधिनियम 26 की धारा 9(1) में बताए गए प्रश्न की सीमा तक, निपटान अधिकारी और न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार विशिष्ट है। लेकिन सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का यह बहिष्कार दो सीमाओं के अधीन होगा। सबसे पहले, सिविल अदालतों के पास उन मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है जहां अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। दूसरा, वैधानिक न्यायाधिकरणों की शक्तियों की सटीक सीमा के संबंध में है।"

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबसे आधिकारिक घोषणा मैसर्स में की गई थी। कैरमला मिल्स लिमिटेड वी बॉम्बे राज्य (6), 7-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नानुसार। -

"* * * x जब भी इससे पहले आग्रह किया जाता है:

सिविल न्यायालय ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र को नागरिक प्रकृति के दावों पर विचार करने के लिए या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है, न्यायालय स्वाभाविक रूप से इस पर विचार करने के लिए इच्छुक महसूस करता है कि क्या एक विशेष क़ानून द्वारा निर्धारित वैकल्पिक प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया उपाय पर्याप्त या पर्याप्त है। ऐसे मामलों में जहां सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, प्रश्न में क़ानून की योजना और इसके द्वारा प्रदान किए गए उपायों की पर्याप्तता या पर्याप्तता पर विचार प्रासंगिक हो सकता है लेकिन निर्णायक नहीं हो सकता है। लेकिन जहां बहिष्करण को आवश्यक निहितार्थ के रूप में पेश किया जाता है, ऐसे विचार बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और संभावित परिस्थितियों में, निर्णायक भी बन सकते हैं। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और उस अधिकार और दायित्व के निर्धारण के लिए विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जाने का प्रावधान करता है और यह आगे बताता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न होंगे। इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद, यह जांच करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सिविल अदालतों में आम तौर पर कार्रवाई से जुड़े उपचार उक्त क़ानून द्वारा निर्धारित हैं या नहीं।"

राम स्वरूप और अन्य बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर फिर से विस्तार से विचार किया। शिकार चंद अन्य (7)। इस मामले में धारा 3(4) और 16 के प्रावधान यूपी के (अस्थायी) किराया नियंत्रण एवं बेदखली अधिनियम 1947 विचाराधीन थे। हालाँकि उक्त धारा के प्रावधान स्पष्ट रूप से सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाते हैं, फिर भी यह माना गया कि यदि आदेश वैधानिक प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था तो आदेश सिविल अदालत में चुनौती के लिए खुला होगा। पैराग्राफ 12 और 13 जिसमें अनुपात और निर्धारित सटीक नियम शामिल हैं, इस प्रकार पढ़ें: -

"सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार के बारे में सवाल से निपटने में अक्सर जिन बिंदुओं को प्रासंगिक माना जाता है उनमें से एक यह है कि क्या विशेष क़ानून, जिसके बारे में आग्रह किया जाता है, ऐसे क्षेत्राधिकार को बाहर करता है, ने उस इरादे को इंगित करने वाले स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया है। एक और परीक्षण जो लागू किया जाता है वह है: क्या उक्त क़ानून किसी ऐसे पक्ष को पर्याप्त और संतोषजनक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है जो इसके भौतिक प्रावधान के तहत प्रासंगिक आदेश से व्यथित हो सकता है। इन दोनों परीक्षणों को लागू करने से यह प्रतीत होता है कि धारा 3(4) और धारा 16 में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट हैं। धारा 16 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश, जिस पर उक्त धारा लागू होती है, को किसी भी न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा और उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। यह सिविल न्यायालयों, क्षेत्राधिकार को छोड़कर एक स्पष्ट प्रावधान है। धारा 3(4) स्पष्ट रूप से सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं करती है, लेकिन संदर्भ में, यह निष्कर्ष कि सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर करने का इरादा है, अपरिहार्य प्रतीत होता है। अत: हमें संतोष है कि श्रीमान... गोयल का यह तर्क सही है कि धारा 3(4) और धारा 16 के प्रावधानों में शामिल आदेशों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है।"

हालाँकि, इस निष्कर्ष का मतलब यह नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट, या आयुक्त, या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश की वैधता के खिलाफ याचिका कभी भी सिविल अदालत में नहीं उठाई जा सकती है। हमारी राय में, सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा बनाई गई रोक उन मामलों में लागू नहीं हो सकती है, जहां सिविल अदालत के समक्ष उठाई गई याचिका मामले की जड़ तक जाती है और यदि बरकरार रहती है, तो निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। कि आक्षेपित आदेश निरर्थक है। उदाहरण के लिए, एक आदेश के मामले को एक ऐसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया माना जाता है जो कानूनन जिला मजिस्ट्रेट नहीं है। यदि यह किसी पार्टी द्वारा महाभियोग चलाकर दिखाया जाता है, सिविल कोर्ट में आदेश की वैधता यह है कि आदेश ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित किया गया था जो जिला मजिस्ट्रेट नहीं था, कानून में आदेश अमान्य होगा और ऐसी याचिका को अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है सिविल कोर्ट. इसी प्रकार, यदि किसी मकान मालिक को अनुमति देने का आदेश एक जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है, जब विचाराधीन संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो एक पक्ष सिविल कोर्ट के समक्ष आग्रह करने का हकदार होगा कि आई-अनुमति की आवश्यकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति पूरी तरह से अमान्य है और कानून में अमान्य है। आइए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक और मामला लेते हैं। यदि धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, मकान मालिक को अपने किरायेदार पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, तो वह किरायेदार को नोटिस जारी करेगा और मकान मालिक के आवेदन को गुण-दोष के आधार पर निपटाने से पहले उसे अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगा। और ऐसे वैधानिक प्रावधान के सामने, जिला मजिस्ट्रेट किरायेदार को नोटिस जारी किए बिना एक पक्षीय अनुमति देता है, ऐसे मामले में निर्धारित अनिवार्य प्रावधान का पालन करने में जिला मजिस्ट्रेट की विफलता उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देगी। पूरी तरह से अमान्य और यह दलील कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन किए बिना एक आदेश पारित किया गया है, सिविल अदालत के समक्ष परीक्षण के लिए खुला रहेगा। इसी तरह, ऐसे वैधानिक प्रावधान के अभाव में, यदि यह माना जाता है कि धारा 3 द्वारा विचार किए गए उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही अर्ध न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में है और उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आजमाया जाना चाहिए और यह है यह दिखाया गया है कि किसी दिए गए मामले में ऐसे आदेश से प्रभावित पक्ष को नोटिस दिए बिना एक आदेश पारित किया गया है, यह उक्त पक्ष के लिए यह तर्क देने के लिए खुला होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित एक आदेश अमान्य है और इसका

अस्तित्व होना चाहिए सिविल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज किया जाना. हमारी राय में, ऐसी याचिका को अधिनियम की धारा 3(4) और धारा 16 में निहित प्रावधानों के कारण बाहर नहीं किया जा सकता है।"

पैराग्राफ 18 में आगे यह देखा गया कि मेसर्स कमला मिल्स मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्णय उनके द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है। इस आधिकारिक घोषणा के सामने किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यदि कोई आदेश है

संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए बिना सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अमान्य होगा और सिविल अदालत में चुनौती के लिए खुला होगा, भले ही क़ानून स्पष्ट रूप से वैधता को चुनौती देने के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता हो। या ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता। इस प्रश्न पर धूलाभाई आदि मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक बार फिर विचार किया गया। वी मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, (8) और विद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले में निहित सात सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। मैसर्स कमला मिल के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों का दायरा और निर्धारित नियम बेंच के विशेष विचार के तहत आया और यह देखा गया कि विशेष बेंच (मैसर्स कमला मिल्स मामले में) ने इसे स्वीकार करने से परहेज किया। मास्क कंपनी के मामले (8) का आदेश या इसे खारिज करना, इस आशय से कि भले ही अधिकार क्षेत्र को अधिकारियों के निर्णय को अंतिम बनाने वाले प्रावधान से बाहर रखा गया हो, सिविल अदालतों के पास उन मामलों की जांच करने का क्षेत्राधिकार है जहां विशेष अधिनियम के प्रावधान नहीं हैं के साथ अनुपालन। क़ानून के प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में विशेष क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करने के सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस प्रकार बरकरार रखा गया, भले ही वैधता या वैधता पर सवाल उठाने का सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हो। ट्रिब्यूनल के आदेशों को क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया था।

(7) यद्यपि अमर सिंह के मामले में निर्धारित नियम के अनुसार (सुप्रा) उत्तरदाताओं को कलेक्टर के आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील या समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, जिसमें वे पक्षकार नहीं थे, लेकिन फिर भी यदि यह तर्क के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि वे अपीलीय प्राधिकारी की अनुमति से अपील दायर कर सकते हैं या समीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित आदेश की घोषणा प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने का समवर्ती या वैकल्पिक उपाय है जहां तक उनका संबंध है, उन्हें पंजाब अधिनियम की उक्त धारा 25 के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया जाएगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैकल्पिक या समवर्ती उपचारों के मामले में व्यक्ति उनमें से किसी एक को चुनने के लिए खुला है। इसलिए, अधिनियम के तहत उपचार का अस्तित्व, यदि कोई हो, मुकदमे के उपचार पर रोक नहीं लगाएगा यदि यह अन्यथा उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध था। राज्य के विद्वान वकील द्वारा एक भी मामले का हवाला नहीं दिया जा सका,वह रोक जिसमें यह माना जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मुकदमे का उपचार जो आदेश का पक्षकार नहीं है और न ही उसे कोई नोटिस दिया गया है, यह घोषणा करने के लिए कि ऐसा आदेश गैर-स्थायी था जहां तक उसका संबंध था। भले ही पारित आदेशों की वैधता और वैधानिकता को स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि क़ानून के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया वे सभी ऐसे थे जिनमें मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जो विशेष क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के समक्ष एक पक्ष था। इसलिए, उन सभी निर्णयों में की गई टिप्पणियाँ; वहां उपलब्ध स्थिति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इनमें से किसी भी निर्णय में, जैसा कि धौंकल शेओ राम के मामले (सुप्रा) में देखा गया, मास्क कंपनी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी। इसलिए, हम यह मानेंगे कि वर्तमान मुकदमा पंजाब अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं था और पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
कुरुक्षेत्र